

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक:वि.जा.प्र./2022/ 3 2763-804

दिनांक 25-8-2022

उप महानिरीक्षक कारागार  
रेज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।  
समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/  
कारागृह/सुधारगृह, राजस्थान।

विषय:- आपराधिक प्रकरणों में समान प्रकृति के आरोपों में आपराधिक  
कार्यवाही एवं विभागीय जांच साथ-साथ किये जाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(157)/  
कार्मिक/का-3/97 दिनांक 30.08.2017 एवं परिपत्र क्रमांक प.2(157)/का/का-3/  
शिका/97 दिनांक 22.04.2019 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग  
द्वारा जिन लोक सेवकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में विभागीय  
आचरण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध  
आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय जांच की कार्यवाही भी किये जाने  
हेतु निर्देशित किया गया है, की छायाप्रति (जरिये ई-मेल) संलग्न प्रेषित कर  
लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में राज्य सरकार के परिपत्रों में वर्णितानुसार  
आवश्यक कार्यवाही करावे।

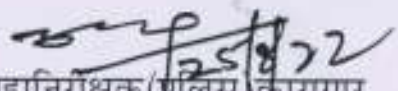
संलग्न:- उपरोक्तानुसार (ई-मेल द्वारा)

भवदीय

— sd —  
( यू. एल. छानवाल )  
महानिरीक्षक(पुलिस)कारागार  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
2. अधीक्षक ग्रेड-II, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, मुख्यालय कारागार, जयपुर को वास्ते अपलोड हेतु।

  
महानिरीक्षक(पुलिस)कारागार  
राजस्थान, जयपुर

और प्रारम्भिक न्याय का तथ्याक्त यह है कि—सम्बन्धित व्यक्ति को कारण दर्शित करने विषयक अवसर दिया जावे। इसके बिना कोई आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है।<sup>1</sup>

**प्रतिकूलता स्वतः कारित—**नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का इनन होने पर प्राप्ती को हुई प्रतिकूल हानि (प्रीज्यूडिस) को चलाया जाता है, तथा न्यायालय उसे मरद करके है, परन्तु उच्चतम न्यायालय के नवीनतम मत के अनुसार—“नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं करना अपन आप में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकूलता है और नैसर्गिक न्याय के इनन के अलावा इस प्रतिकूलता के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।”<sup>2</sup>

**जांच जब नाममात्र (Sham) की—** जांच स्थान 'क' के लिये नोटिस दिये गये। अन्वयक उसे स्थान 'ख' पर बदलने को अल्पवर्धि सूचना दी गई, जिससे प्राप्ती अपने गवाह पेश नहीं कर सका। ऐसी जांच नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन मानी गई और दण्डाज्ञा अपास्त की गई।<sup>3</sup>

**जब पूर्ण अवसर दिया गया—**नैसर्गिक न्याय की अनुपालना हो गई—(नियम 14, 16)—जब अनुसामनिक-प्राधिकारी ने प्रत्येक आरोप पर विम्बुत आदेश पारित किया और संघ से हटाने का दण्ड दिया और एकल न्यायाधीश ने उस पर रिट याचिका को पूर्ण अवसर दिये जाने के आधार पर खारिज कर दिया, तो अपील में खण्डपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त कर मामले को पुनः जांच के लिए वापस भेज दिया। उच्चतम न्यायालय ने खण्डपीठ के निर्णय को अपास्त कर दिया, क्योंकि आरोपित अधिकारी को पूर्ण अवसर दे दिया गया था। [1990 (1) स.ला.रि. 1 (खण्डपीठ) को फलत दिया reversed।<sup>4</sup>

**नैसर्गिक न्याय-विभागीय जांच—“सकारण आदेश” के अर्थ की समीक्षा—**सारभूत/पर्याप्त पालना आवश्यक — उपलब्ध सामग्री पर प्राधिकारी को सम्पूर्ण रूप से मनाविधि करना होगा और फिर अपने निष्कर्ष के कारण लिखने होंगे। आरोपित द्वारा अभ्यावेदन में उदाये गये तर्कों को कारण देने हुए स्वीकार या अस्वीकार करना लेखबद्ध किया जायेगा। अभिलेख पर मनाविधि (मस्तिष्क का प्रयोग करना) स्पष्ट साक्षित होगा और दूसरे आरोपित को भेजा जायेगा। केवल फाटल पर लिखना पर्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को सारभूत पालना दर्शित करने होगी। (पैरा 5)<sup>5</sup>

[कृपया आगे नियम 16 (10) की व्याख्या भी देखिये। आगे खण्ड (3) में अध्याय (5) व (6) भी देखिये।]

## 7. अभिचोजन एवं विभागीय जांच

### [ Prosecution & Departmental Enquiry ]

#### राजस्थान सरकार के नवीनतम अनुदेश

“उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये गये सम्स्त परिपत्रों/निदेशों का अभिक्रमण करते हुए यह निर्दिष्ट किया जाता है कि—ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध पीठवारी मुकदमा न्यायालय में विधाराधीन है और साथ ही विभागीय अनुसामनिक कार्यवाही भी आरम्भ की गई है, तो

- 1 राजस्थान राज्य च. क.आ. ए.ओ. और संशोधन संघ महत्ता 1973 (1) उम.वि.प. 264 = 1973 सु.को.क. (ले.स.) 63 ; ए.आई.आर. 1973 सु.को. 834 ; (1973) 1 सु.को.क. 120
- 2 एम्. एल. चक्रवर्ती जन्मोत्सव : 1963) 2 सु.को.क. 379 ; ए.आई.आर. 1981 सु.को. 136
- 3 मुरारी मोहनदीव च. संविध. उदा. संवत्तर 1985 (2) स.ला.रि. 170 (सु.को.)
- 4 राजस्थान राज्य च. संघ.क. सं. सं. 1993 (2) उदा. पालन जन्मोत्सव 368 ; 1993 (2) स.ला.रि. 281 (सु.को.) ; 1993 (2) उम.वि.प. 151
- 5 प्रभुपाल अग्रवाल च. राज्य. 1941 ; स.ला.क. 464-1991 (2) स.ला.रि. 630-1993 (1) स.ला.क. 525
- 6 सं. सं. 23 (36) विधुलि.क. व. [1] रि. 2 63 संघ. सं. सं. 5 (17) विधुलि.क. 3) 66 रि. 2) 9-1968

न्यायालय द्वारा मुकदमे की का-वही पूर्ण होने से पूर्व भी विभागीय जांच के मामले में अन्तिम निर्णय लेने में कोई रुकावट नहीं है, चाहे उक्त दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में आरोप समान हों।<sup>1</sup>

(3) भारत सरकार ने भी इस बारे में इसी प्रकार के अनेक निर्देश<sup>2</sup> समय-समय पर दिये हैं। विभागीय जांच तथा द्राष्टिक अभियोजन दोनों साथ-साथ चलाने में कोई बाधनी बाधा नहीं है।<sup>3</sup> एक बार मामला न्यायालय में दे दिया गया है; तो यह उचित होगा कि विभागीय जांच को स्थगित कर दिया जाये। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दोनों कार्यवाहों साथ-साथ चल सकती है।<sup>4</sup> एक मत यह है कि—जब तक फौजदारी आरोप विद्यमान है, विभागीय जांच शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।<sup>5</sup> परन्तु उच्चतम न्यायालय के मतानुसार यदि विभागीय जांच विधि द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के दुराचरण के लिए सरकार को किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करती है, तो फौजदारी कार्यवाही अलग से स्थापित की जा सकती है।<sup>6</sup> परन्तु न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षित कर लेनी चाहिये, ताकि कर्मचारी के पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।<sup>7</sup>

एक घटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच व फौजदारी मुकदमा दोनों साथ-साथ चले। उसे विभागीय जांच में सेवा से हटा दिया गया, पर फौजदारी मुकदमे में उसे धरो कर दिया गया। फौजदारी न्यायालय और विभागीय जांच में साक्ष्य की भिन्नता व पर्याप्तता के कारण ऐसा हो सकता है। अतः संवैधानिक की आज्ञा अवैध मानी गई।<sup>8</sup>

द्राष्टिक अभियोजन (मुकदमा) में प्रार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया, पर समान आरोपों पर साथ-साथ चल रही विभागीय जांच में उसे दोषी ठहरा कर पदच्युत कर दिया गया। टी.श्री. चावड़ा बनाम मैसूर राज्य (रिट याचिका 693 of 1970 दिनांक 13-12-73) में पूर्णपोट ने निर्धारित किया कि—“द्राष्टिक अभियोजन में दोषमुक्त होने से विभागीय जांच करने में कोई बाधा नहीं है तथा जांच अधिकारी ऐसी जांच से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।” अतः रिट खारिज की गई।<sup>9</sup>

आपराधिक (फौजदारी) अभियोजन तथा विभागीय जांच—केवल जाणबुझकर बदनिश्चय से किये गये फुल्प (COMMISSION) के लिए फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है, परन्तु भूल या कार्य के लिए जो निर्णय की त्रुटि या ठीक चार्ज न चरने या जल्दयाजी चरने या असावधानी या तरोके की अदक्षता आदि के

1. इपोक एम. 9-1631 कार्मिक 1-क 3/77 दिनांक 11 सितम्बर 1978—(सेरविज 1978 पृष्ठ 289)

2. G.L. M. H.A., O.M. No. 39/30/54 Est. dated 7th, June 1955; Even No. dated 20th October 1955; No. 39/8/64 Est. (A) dated 4-9-1964.

3. जगदीश प्रसाद खत्री व. राजस्थान राज्य 1960 ले.ड.क. (नॉर्म) 132 राज. : (1960) 1 स.न्या. रि. 225 : 1979 स.न्या.को. : 1979 स.न्या.को. 582; ए.आई.आर. 1960 सु.को. 826 : 1965 सु.को. 155, 1969 ले.ड.क. 194 (सु.को.) पर विचार कर प्रयोग में लाया गया।

4. भगत सिंह व. राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1960 सु.को. 3210, राधा प्रदेव व. उत्तरप्रदेश ए.आई.आर. 1958 स.प. 325, कल्प नारायण व. महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1956 पदम 462, अंगम व. गुजरात अधीन 1968 स.न्या.रि. 176 (मैसूर), 1968 ले.ड.क. 1145 (मनीपुर), ए.आई.आर. 1968 पदम 300 : 1968 ले.ड.क. 63 (पदम)

5. ए.आई.आर. 1957 उद्दीम 52, 1952 गंगपूर 170, 1954 गंगपूर 229

6. राधा ए. वेकटरमण व. भारत सभ ए.आई.आर. 1954 सु.को. 375

7. दिल्ली कराव सिंग व. गुजरात राज्य ए.आई.आर. 1960 सु.को. 806

8. नूरीशम व. भारत सभ 1974 ले.ड.क. 553 (हि.प.) : 1973 11 स.न्या.रि. 564

9. चरणलाल व. कर्नाटक राज्य 1961 (1) स.न्या.क. 78 (फौजदारी)

राजस्थान जयपुर दिनांक 25-8-2022

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
Department of Personnel (A-3)

No.F.2(157)/Karmik/Ka-3/97

Jaipur, Dated: 13 0 AUG 2017

All Additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries to Government  
All Heads of Departments (including District Collectors)  
All Special Secretaries, Deputy Secretaries to Govt.

**CIRCULAR**

**Subject:** Criminal proceedings and departmental enquiry –whether both can be initiated and continued on same set of charges and allegations.

On the subject mentioned above, attention is invited towards department Circulars dated Aug 08, 2001 and Aug 09, 2001.

Vide Circular dated Aug 08, 2001, clarification has been issued that departmental and criminal proceedings can go on simultaneously. The departmental proceedings should be stayed only in case the charges are grave, the matter involves complex questions of law of fact and the continuation of the departmental proceedings will seriously prejudice the defence of the delinquent in the trial court.

Circular dated Aug 09, 2001, dwells on the question as to whether charges pertaining to criminal offenses by employees can be identical in criminal proceedings and departmental enquiry.

It has been observed that in many cases, chargesheets under relevant disciplinary rules are not being issued despite clear *prima facie* evidence of misconduct on the ground that the matter is under investigation or against whom a chargesheet is filed in a court. The matter has engaged the attention of Government of India also and DoPT, Government of India has issued OM. numbered FNO 11012 /6/2007 – Estt (A-III) dated 21<sup>st</sup> July, 2016 in this regard.

Taking a cue from the above mentioned OM, in supersession of earlier orders dated Aug 08, 2001 and Aug 09, 2001, the following issues are hereby clarified, in this regard:-

- (i) Issue of charge sheet and continuation of departmental proceedings against an officer against whom an investigating agency is conducting investigation or against whom a charge sheet has been filed in a court.
- (ii) Effect of acquittal in a criminal case on departmental inquiry.

**Issue of charge sheet and continuation of departmental proceedings against an officer against whom an investigating agency is conducting investigation or against whom a charge sheet has been filed in a court**

It has been reaffirmed in a catena of cases that there is no legal bar in law for initiation of simultaneous criminal and departmental proceedings on the same set of allegations. The Hon'ble Supreme Court in *State of Rajasthan vs BK Meena & Ors. (1996) 6 Supreme Court Cases 417* has emphasised the need for initiating departmental proceedings in such cases in these words –

*"It must be remembered that interests of administration demand that the undesirable elements are thrown out and any charge of misdemeanor is enquired into promptly. The disciplinary proceedings are meant not really to punish the guilty but to keep the administrative machinery unsullied by getting rid of bad elements. The interest of the delinquent officer also lies in a prompt conclusion of the disciplinary proceedings. If he is not guilty of the charges, his honour should be vindicated at the earliest possible moment and if he is guilty, he should be dealt with promptly according to law. It is not also in the interest of administration that persons accused of serious misdemeanor should be continued in office indefinitely, i.e., for long periods awaiting the result of criminal proceedings."*

In *Capt. M. Paul Anthony vs. Bharat Gold Mines Ltd. & Anr., (1999) 3 SCC 679*, the Supreme Court has observed that departmental proceedings and proceedings in a criminal case can proceed simultaneously as there is no bar in their being conducted simultaneously, though separately. The following broad principles for application in the facts and circumstances of the given case have been laid down in this judgement regarding the continuation of departmental proceedings while judicial proceedings are being pursued in the court -

*"(i) Departmental proceedings and proceedings in a criminal case can proceed simultaneously as there is no bar in their being conducted simultaneously, though separately.*

*(ii) If the departmental proceedings and the criminal case are based on identical and similar set of facts and the charge in the criminal case against the delinquent employee is of a grave nature which involves complicated*

questions of law and fact, it would be desirable to stay the departmental proceedings till the conclusion of the criminal case.

(iii) Whether the nature of a charge in a criminal case is grave and whether complicated questions of fact and law are involved in that case, will depend upon the nature of offence, the nature of the case launched against the employee on the basis of evidence and material collected against him during investigation or as reflected in the charge sheet.

(iv) The factors mentioned at (ii) and (iii) above cannot be considered in isolation to stay the departmental proceedings but due regard has to be given to the fact that the departmental proceedings cannot be unduly delayed.

(v) If the criminal case does not proceed or its disposal is being unduly delayed, the departmental proceedings, even if they were stayed on account of the pendency of the criminal case, can be resumed and proceeded with so as to conclude them at an early date, so that if the employee is found not guilty his honour may be vindicated and in case he is found guilty, administration may get rid of him at the earliest."

Here even though not the subject matter of this Circular yet because of its importance, it is considered apposite to mention that sometimes from the same facts and circumstances from which a criminal charge is constituted, additional or different charges and allegations of misconduct which are punishable under the RCS (CCA) Rules, may also be made out. Examples of this have been given in the Circular dated Aug 09, 2011 and these should be included in the departmental charge sheet.

#### **Effect of acquittal in a criminal case on departmental inquiry**

The question as to what is to be done in the case of acquittal in a criminal case has been answered by the Hon'ble Supreme Court in R.P. Kapur vs. Union of India & Anr. AIR 1964 SC 787 (a five Judge bench judgement) as follows: If the trial of the criminal charge results in conviction, disciplinary proceedings are bound to follow against the public servant so convicted. Even in case of acquittal proceedings may follow where the acquittal is other than honourable.

The issue was explained in the following words by the Hon'ble Supreme Court in Ajit Kumar Nag v G M, (PJ), Indian Oil Corporation Ltd., (2005) 7 SCC 764.

*"Acquittal by a criminal court would not debar an employer from exercising power in accordance with Rules and Regulations in force. The two proceedings criminal and departmental are entirely different. They operate in different fields and have different objectives. Whereas the object of criminal*

*trial is to inflict appropriate punishment on offender, the purpose of enquiry proceedings is to deal with the delinquent departmentally and to impose penalty in accordance with service Rules. In a criminal trial, incriminating statement made by the accused in certain circumstances or before certain officers is totally inadmissible in evidence. Such strict rules of evidence and procedure would not apply to departmental proceedings. The degree of proof which is necessary to order a conviction is different from the degree of proof necessary to record the commission of delinquency. The rule relating to appreciation of evidence in the two proceedings is also not similar. In criminal law, burden of proof is on the prosecution and unless the prosecution is able to prove the guilt of the accused 'beyond reasonable doubt', he cannot be convicted by a court of law. In departmental enquiry, on the other hand, penalty can be imposed on the delinquent officer on a finding recorded on the basis of 'preponderance of probability'. Acquittal of the appellant by a Judicial Magistrate, therefore, does not ipso facto absolve him from the liability under the disciplinary jurisdiction of the Corporation."*

The judgement of the Hon'ble Supreme Court in G.M. Tank vs State of Gujarat (2006) 5 SCC 446 has reaffirmed the principles laid down in R.P. Kapur (supra). In G.M. Tank case, Court observed that there was not an iota of evidence against the appellant to hold that he was guilty. As the criminal case and the departmental proceedings were based on identical set of facts and evidence, the Court set aside the penalty imposed in the departmental inquiry also.

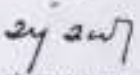
Ratio in the G.M. Tank judgement should not be misconstrued to mean that no departmental proceedings are permissible in all cases of acquittal or that in such cases the penalty already imposed would have to be set aside. What the Hon'ble Court has held that is no departmental inquiry would be permissible when the evidence clearly establishes that no charge against the Government servant may be made out.

The two proceedings criminal and departmental are entirely different. They operate in different fields and have different objectives. Whereas the object of criminal trial is to inflict appropriate punishment on offender, the purpose of enquiry proceedings is to deal with the delinquent departmentally and to impose penalty in accordance with service Rules. In a criminal trial, incriminating statement made by the accused in certain circumstances or before certain officers is totally inadmissible in evidence. Such strict rules of evidence and procedure would not apply to departmental proceedings. The degree of proof which is necessary to order a conviction is different from the degree of proof necessary to record the commission of delinquency.

In view of the law laid down in various judgements, including the ones quoted above, in cases of serious charges of misconduct, particularly involving moral

turpitude, the Departments should keep the following points in view to take prompt action:

- (i) All incriminating documents should be seized promptly to avoid their tempering or destruction of evidence.
  - (ii) Particular care needs to be taken for retention of copies of such documents while handing over the same to an investigating agency. These documents may be attested after comparison with the originals.
  - (iii) In case the documents have been filed in a court, certified copies of documents may be obtained.
  - (iv) Documents and other evidence must be examined to see whether any misconduct, including favour, harassment, negligence or violation of rules/instructions has been committed. If there is a prima facie evidence of misconduct, charge sheet under the appropriate rule must be issued. As there may be certain charges as explained in the Circular dated 9<sup>th</sup> August, 2001 which do not constitute any crime but do constitute misconduct, they must also be included in the charge sheet.
  - (v) Court judgements should be promptly acted upon:
    - (a) in cases of conviction action is to be taken under Rule 19 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958;
    - (b) in cases of acquittal also, if the Court has not acquitted the accused honourably, charge sheet may be issued;
    - (c) an acquittal on technical grounds or where a benefit of doubt has been given to the accused will have no effect on a penalty imposed under Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as while in a criminal trial the charge has to be proved beyond reasonable doubt, in the departmental inquiry the standard of evidence is preponderance of probability.
13. All are requested to bring the above guidelines to the notice of all concerned officials for their benefit.

  
(Sanjay Malhotra)  
Principal Secretary



राजस्थान सरकार  
कार्मिक(क-3/शिका)विभाग

कमाक.प.2(157)का/क-3/शिका/97

जयपुर दिनांक 22.04.2019

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/  
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/  
समस्त संभागीय आयुक्त/  
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)  
समस्त विशिष्ट शासन सचिव/  
संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिवगण।

**परिपत्र**

विषय-आपराधिक प्रकरणों में समान प्रकृति के आरोपों में आपराधिक कार्यवाही एवं विभागीय जांच साथ-साथ किये जाने हेतु परिपत्र दिनांक 30.08.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में।

राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 30.08.2017 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा जिन लोक सेवकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में विभागीय आचरण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय जांच की कार्यवाही भी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, लेकिन राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उक्त परिपत्र दिनांक 30.08.2017 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है।

अतः परिपत्र दिनांक 30.08.2017 के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाते हैं, ऐसे प्रकरणों में संबंधित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करे कि जिन प्रकरणों में प्रथम दृष्टया आचरण नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष स्वयं के स्तर से संबंधित अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श कर अविलम्ब आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करे तथा प्रकरण विभागीय जांच करने योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मय प्रपत्र अ.ब.स.द. राज्य सेवा के अधिकारियों से संबंधित प्रकरणों को कार्मिक (क-3/जाच) विभाग को अविलम्ब प्रस्तुत करावें तथा अधीनस्थ सेवा के कार्मिक की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी स्वयं के स्तर से विभागीय जांच की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(रोली सिंह)

प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।